शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

शुभमन गिल के पास WTC में 3000 रन पूरा करने का भी मौका

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

'वरदान' वाले ट्विस्ट ने बढ़ाई हलचल; 6 सितंबर से होगा ग्रैंड प्रीमियर

Page-05

संसद में फिर हंगामा

बिना चर्चा टैक्स संशोधन बिल पास, राम मंदिर और छात्र प्रदर्शन पर विपक्ष का विरोध

- विपक्ष के हंगामे के बीच 'कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026' लोकसभा से बिना बहस के पारित हो गया।
- विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा मामले और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की, जिससे दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहा।

मानसून सत्र के 14वें दिन भी संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो सका। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में जमकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच लोकसभा ने 'कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026' को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।इस विधेयक के जरिए 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' में भी संशोधन किया गया है। हालांकि, विपक्ष के लगातार विरोध और नारेबाजी के कारण विधेयक पर विस्तृत बहस नहीं हो सकी। मानसून सत्र की शुरुआत से ही लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल को लेकर व्यवधान बना हुआ है, जिससे सदन की नियमित कार्यवाही प्रभावित हो रही है।उधर, राज्यसभा में भी राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इन मामलों पर सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। हंगामे के दौरान राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा कि वह विपक्ष की भावनाओं से गृह मंत्री को अवगत कराएं।दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच नोकझोंक की स्थिति बन गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को अपनी बात रखने का अवसर दिए जाने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। खरगे ने कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है और वह तय करेंगे कि किस मुद्दे पर और किस तरीके से बोलना है।वहीं, किरेन रिजिजू ने विपक्ष की मांग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष पिछले कई दिनों से एक ही मुद्दा उठा रहा है और सदन के नियम इस तरह के निर्देश की अनुमति नहीं देते। इसके बाद सदन में हंगामा और तेज हो गया।राज्यसभा ने इस दौरान 'विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026' को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना है, ताकि 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक हुए खर्च का भुगतान किया जा सके।इस बीच, लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। सदन ने परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।कुल मिलाकर, संसद का एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा की उम्मीद एक बार फिर अधूरी रह गई।

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं पर बवाल,

13वें दिन छात्रों ने मांगा CM हेमंत सोरेन का इस्तीफा

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन गुरुवार को 13वें दिन भी जारी रहा और अब यह प्रदर्शन और तेज हो गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार उनकी शिकायतों और मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है।प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए था। वहीं, कुछ छात्रों ने मुख्यमंत्री की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि केंद्र में परीक्षा से जुड़े विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, तो राज्य सरकार को भी छात्रों की मांगों पर जवाब देना चाहिए।हालांकि, आंदोलन के बीच बातचीत की दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ा है। छात्रों और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों ने सरकार से बातचीत कर विवाद का समाधान निकालने के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गठित किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान के एक दिन बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदर्शनकारियों के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं।'जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच' के बैनर तले यह आंदोलन 25 जुलाई को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, यह हाल के वर्षों में राज्य में छात्रों और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के बड़े आंदोलनों में से एक है। सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आने के बाद मंच ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाने का फैसला किया है। इसमें आठ छात्र, दो विशेषज्ञ और एक अधिवक्ता शामिल हैं।

डीके शिवकुमार बोले- पार्टी में कोई मतभेद नहीं

कर्नाटक कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार पर नाराजगी

कर्नाटक कांग्रेस में हालिया मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के आवंटन के बाद सामने आई नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पार्टी में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस में कोई समस्या नहीं है और सभी नेता पार्टी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।शिवकुमार ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के लिए केवल 33 पद हैं, इसलिए हर इच्छुक विधायक को मंत्री बनाना संभव नहीं है। हालांकि, पार्टी वरिष्ठ नेताओं की भावनाओं और अपेक्षाओं का सम्मान करती है। इसी बीच एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और शिवकुमार ने नाराज नेताओं से मुलाकात कर उनकी चिंताओं पर चर्चा की। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की तरह है और परिवार में शिकायतें होना सामान्य है, लेकिन सभी नेता मिलकर संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते हैं।3 अगस्त को हुए कैबिनेट विस्तार के बाद कई वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं मिलने पर असंतोष सामने आया था। रायचूर ग्रामीण से विधायक बसनागौड़ा दद्दल ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं, विधायक यशवंतरायगौड़ा वी. पाटिल ने मंत्री पद नहीं मिलने पर दिया अपना इस्तीफा वापस ले लिया। कई वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट में जगह न मिलने के बाद क्षेत्रीय और सामुदायिक संतुलन को लेकर भी सवाल उठे।इस बीच डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के ऐतिहासिक लालबाग में फ्लावर शो का उद्घाटन किया। 6 से 17 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन की थीम 'गंगा राजवंश' पर आधारित है।शिवकुमार ने कहा कि सरकार बेंगलुरु में लालबाग जैसे तीन और उद्यान विकसित करने की योजना बना रही है।

तरुण तेजपाल रेप केस में बड़ा फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश पलटा; 10 साल की सजा

गोवा से जुड़े करीब 13 साल पुराने रेप मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने 'तहलका' मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी एक जूनियर सहयोगी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने गोवा की निचली अदालत के उस फैसले को भी पलट दिया, जिसमें मई 2021 में तेजपाल को आरोपों से बरी कर दिया गया था। दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत ने उन्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जमसांडेकर की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के बरी करने के आदेश को निरस्त कर दिया। यह मामला 2013 में गोवा के एक फाइव-स्टार होटल में आयोजित 'थिंकफेस्ट' कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई घटना से जुड़ा है। उस समय पीड़िता तेजपाल की जूनियर सहयोगी के तौर पर काम कर रही थी।मई 2021 में गोवा की फास्ट-ट्रैक अदालत ने तेजपाल को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद गोवा सरकार ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लंबे समय से चल रहे इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला अब महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।सुनवाई के दौरान तेजपाल ने खुद को 'राजनीतिक प्रताड़ना का शिकार' बताया और अदालत से सजा में नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने अपने परिवार और दो बेटियों का हवाला देते हुए अदालत से सहानुभूति की मांग की। वहीं, गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि सजा के जरिए यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि सहमति के बिना किसी भी तरह का यौन संबंध स्वीकार्य नहीं है।यह मामला उस दौर में सामने आया था, जब देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर व्यापक बहस चल रही थी। इस केस ने खास तौर पर कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, शिकायत दर्ज कराने में आने वाली चुनौतियों और नौकरी या प्रताड़ना के डर जैसे मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 23 देशों की यात्राओं पर 187 करोड़ रुपये खर्च हुए

छह अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्ष 2025 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और जापान समेत 23 देशों की यात्राओं पर 180 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। विदेश मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को लेकर देशवार और वर्षवार आंकड़े साझा किए गए। इसके अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर करीब 74.58 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसमें छह से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा भी शामिल है। आप के संजय सिंह और माकपा के वी. शिवदासन ने विदेश मंत्रालय से 2021 से अब तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का देशवार विवरण और इन यात्राओं पर हुए खर्च का वर्षवार एवं यात्रा-वार ब्योरा मांगा था। विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा ने अपने जवाब में प्रधानमंत्री द्वारा 2021 से की गई विदेश यात्राओं और प्रत्येक यात्रा पर हुए कुल खर्च का वर्षवार तथा यात्रा-वार विवरण दिया।

झारखंड छात्र आंदोलन पर तेजस्वी की चुप्पी

बोले- कल करेंगे बात; बिहार में अपराध पर सरकार को घेरा

झारखंड में छात्रों के जारी आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने संक्षेप में कहा कि इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे और शुक्रवार को अपनी बात रखेंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने मुख्य रूप से बिहार की कानून-व्यवस्था और बंटी यादव हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा।झारखंड में छात्रों का आंदोलन पिछले कई दिनों से चर्चा में है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी गठित किया है। राज्य सरकार की ओर से भी बातचीत की पेशकश की गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव से जब झारखंड के आंदोलन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज किया।वहीं, बिहार के बंटी यादव हत्याकांड को लेकर तेजस्वी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बंटी यादव ने कथित सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। तेजस्वी ने मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिवार को डीजीपी से मुलाकात के लिए समय दिलाया गया था, जिसके बाद कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि कुछ अब भी फरार हैं।तेजस्वी ने बंटी यादव के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मदद का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि बंटी यादव की दो बेटियों और एक बेटे की 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई का पूरा खर्च उनकी पार्टी उठाएगी। इसके लिए परिवार को पांच लाख रुपये का चेक भी दिया गया है। उन्होंने सरकार से बंटी यादव की पत्नी को सरकारी नौकरी देने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने दिनारा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मजदूरी मांगने गए एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। उन्होंने सीवान में हुई फायरिंग और एक अन्य हत्या के मामले को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे।

तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगी और अपराध के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगती रहेगी। अब झारखंड छात्र आंदोलन पर तेजस्वी की विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना! वापसी के ऐलान से गरमाई सियासत, गिरफ्तारी पर भी चर्चा

शेख हसीना ने अगस्त 2024 में सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया है।उनके इस फैसले पर BNP ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर उन्हें अपने निर्णय पर भरोसा है तो उन्हें अभी वापस लौटना चाहिए।हसीना की वापसी के साथ गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर बांग्लादेश में बहस तेज हो गई है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का ऐलान करते ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई हैं। उनकी वापसी को लेकर बांग्लादेश में सियासी माहौल गर्म हो गया है। इस मुद्दे पर 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' (BNP) ने साफ कहा है कि अगर हसीना को अपने फैसले पर भरोसा है तो उन्हें दिसंबर तक इंतजार नहीं करना चाहिए। इसी बयान के बाद उनकी घर वापसी पर गिरफ्तारी और स्वागत की चर्चा शुरू हो गई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार और B N P नेता सैयद मोअज्जम हुसैन अलाल ने शेख हसीना के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर हसीना ने देश लौटने का मन बना लिया है तो उन्हें अभी वापस आ जाना चाहिए। अभी सिर्फ अगस्त का महीना है। फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक इंतजार क्यों? उन्होंने आगे कहा कि हसीना के भविष्य का फैसला बांग्लादेश की जनता, अदालत और प्रशासन करेगी। उनके देश लौटने के बाद यह तय होगा कि उनका स्वागत होगा या उन्हें जेल जाना पड़ेगा। दरअसल, बीते कल बुधवार को शेख हसीना ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया। अगस्त 2024 में सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद यह उनका पहला बड़ा सार्वजनिक बयान था। उन्होंने कहा कि वह अपने लोगों से दूर नहीं रह सकतीं। घर लौटने पर गिरफ्तारी, जेल या जान से मारने की धमकी सहित किसी भी नतीजे का सामना करने के लिए तैयार हैं। जो भी किस्मत होगा देखा जाएगा। मैं दिसंबर में वापस जाना चाहती हूं। बता दें पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को 2024 में जुलाई-अगस्त के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। वहीं, इस मामले में सरकारी गवाह बने पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को पांच साल की जेल की सजा दी गई। ऐसे में फैसला आने के बाद बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना और असदुज्जमां खान कमाल को जल्द से जल्द बांग्लादेश सौंपने की अपील भी की थी। अब सबकी नजर दिसंबर पर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि शेख हसीना तय समय पर बांग्लादेश लौटती हैं या नहीं। अगर लौटती हैं, तो उनका स्वागत होगा या उन्हें कानूनी कार्रवाई (जेल) का सामना करना पड़ेगा। इसका जवाब आने वाले महीनों में बांग्लादेश की राजनीति तय करेगी।

27 राज्यों में जानलेवा फंगस 'कैंडिडा ऑरिस' के मामले

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका में कैंडिडा ऑरिस के बढ़ते मामलों ने मेडिकल एक्सपर्ट की चिंता बढ़ा दी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने बताया है कि इस साल अब तक अमेरिका के 27 राज्यों में खतरनाक फंगस 'कैंडिडा ऑरिस' का स्ट्रेन पाया गया है। दवाओं के असर ना करने (ड्रग रेजिस्टेंस) और असरदार वैक्सीन या इलाज की कमी ने कैंडिडा ऑरिस को गंभीर चिंता का विषय बना दिया है।कैंडिडा ऑरिस (कौरिस) एक तरह का यीस्ट है, जो गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। यह उन लोगों में आसानी से फैलता है जो हेल्थकेयर सेंटर्स में गंभीर रूप से बीमार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने इसे 'क्रिटिकल-प्रायोरिटी फंगल पैथोजन' (बहुत खतरनाक फंगस) माना है। यह कई तरह के इन्फेक्शन का कारण बन सकता है।अमेरिका की नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने बताया कि 25 जुलाई तक इसके 3,437 मामले आए हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 4,290 था। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा मामले (873) दर्ज किए गए। इसके बाद टेक्सास (433) और टेनेसी (283) का नंबर आता है। CDC के अनुसार, हर साल कैंडिडा ऑरिस के मामलों की दर बढ़ रही है लेकिन 2022 से बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है।कोरियाई रिसर्चर्स ने सबसे पहले 1996 में इसकी खोज की थी। यह एक फैलने वाली बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से या अप्रत्यक्ष रूप से दूषित सतहों के जरिए फैलती है। इसके अलावा यह फंगस सतहों और चीजों पर लंबे समय तक बना रह सकता है और मरीजों में फैल सकता है।

डिजिटल पेमेंट तरीकों पर चार्ज लगाने की इजाज़त देने का अधिकार

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

लोकसभा ने गुरुवार को 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' में एक अहम संशोधन पास किया। इससे केंद्र सरकार को बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (U P I) ट्रांज़ैक्शन और दूसरे नोटिफाइड डिजिटल पेमेंट तरीकों पर चार्ज लगाने की इजाज़त देने का अधिकार मिल गया है। हालांकि, इस संशोधन से तुरंत कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन यह उस कानूनी रुकावट को हटाता है जो बैंकों को ऐसे ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूलने से रोकती थी। लोकसभा ने 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026' को ध्वनि मत से पास किया। सदन की कार्यवाही पहले स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई, लेकिन हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के इस बिल को मंज़ूरी दे दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल पेश किया था, जिसका मकसद 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007', 'इनकम टैक्स एक्ट, 2025' और 'फाइनेंस एक्ट, 2026' में संशोधन करना है। यह संशोधन 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट' की धारा 10A के तहत मौजूदा प्रावधान की जगह लेता है। बिल में कहा गया है: "'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' की धारा 10A में, 'इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 269SU के तहत बताए गए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के तरीके' शब्दों, अंकों और अक्षरों की जगह, 'इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का एक या ज़्यादा तरीका, जिसे केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के ज़रिए बताए' शब्द जोड़े जाएंगे। यह बदलाव ऑफिशियल गजट में इस एक्ट के पब्लिश होने की तारीख से लागू होगा।" आसान शब्दों में कहें तो, यह संशोधन केंद्र सरकार को यह तय करने का कानूनी अधिकार देता है कि भविष्य में किन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तरीकों पर चार्ज लगाया जा सकता है। इस बिल के पास होने से UPI ट्रांज़ैक्शन पर अपने-आप चार्ज नहीं लग जाएंगे। बल्कि, यह सरकार को अधिकार देता है कि वह भविष्य में अलग नोटिफिकेशन के ज़रिए बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को चार्ज लगाने की इजाज़त दे सके।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ले जा रहा हेलिकॉप्टर यात्री विमान के काफी करीब पहुंच गया

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ले जा रहा मिलिट्री हेलिकॉप्टर हेलीकॉप्टर मंगलवार को वॉशिंगटन में एक यात्री विमान के काफी करीब पहुंच गया। यह घटना रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुई। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। अब अमेरिकी एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं कि आखिर यह स्थिति पैदा ही क्यों हुई और चूक किसकी थी।घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे की है। राष्ट्रपति ट्रंप का हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस के पास एलिप्स से ज्वाइंट बेस एंड्रयूज के लिए रवाना हुआ था। इसके करीब एक मिनट बाद Envoy Air का एक पैसेंजर प्लेन E-170 रीगन नेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर निकला। पैसेंजर प्लेन के गुजरने के कुछ ही देर बाद ट्रंप का हेलीकॉप्टर भी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा। दोनों प्लेन एक-दूसरे से तय सुरक्षा दूरी से बहुत कम अंतर पर आ गए थे। हालांकि, इस घटना में डोनाल्ड ट्रंप या पैसेंजर प्लेन में सवार लोगों को कोई तत्काल खतरा नहीं हुआ। नियमों के मुताबिक, इस इलाके में उड़ रहे विमानों के बीच कम से कम 1.5 मील की सीधी दूरी और 500 फीट की ऊंचाई का अंतर होना चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों की शुरुआती जांच में यह पता चला है कि दोनों विमान सीधे एक-दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन उनके बीच तय दूरी से कम अंतर जरूर रह गया था। वहीं, व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति को कभी कोई खतरा नहीं था। मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों के हवाले से 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मंगलवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के साथ बातचीत में गड़बड़ी के बाद, 'मरीन वन' अमेरिकी राजधानी के ऊपर एक पैसेंजर प्लेन के एक मील से भी कम दूरी पर आ गया था।

अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी मनाई गई

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

जापान के हिरोशिमा शहर में अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु बम हमले की बृहस्पतिवार को 81वीं बरसी मनाई गई। इस अवसर पर शहर के महापौर काजुमी मात्सुई ने प्रमुख शक्तियों द्वारा युद्ध का सहारा लेने की आलोचना की और परमाणु हथियारों को प्रतिरोधक क्षमता के साधन के रूप में उचित ठहराने की प्रवृत्ति समाप्त करने का आह्वान किया। हिरोशिमा शांति स्मारक पार्क में आयोजित समारोह में अपने शांति संदेश में मात्सुई ने कहा कि परमाणु हथियारों की अमानवीयता को कम करके आंकना और अपनी समृद्धि के लिए बल प्रयोग को स्वीकार करना हिंसक प्रतिशोध के ऐसे चक्र को जन्म दे सकता है, जिसका अंत एक और हिरोशिमा या नागासाकी जैसी त्रासदी में हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज भी अनेक राजनीतिक नेता परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को व्यावहारिक नीति मानते हैं और हिंसा को वैध ठहराते हैं। उनके अनुसार, इससे परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व का लक्ष्य और दूर होता जा रहा है। उन्होंने लोगों से अतीत से सीख लेकर शांति के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की। समारोह में अमेरिका और ईरान सहित लगभग 120 देशों और क्षेत्रों के

प्रतिनिधियों समेत करीब 50,000 लोगों ने भाग लिया। सुबह 8 बजकर 15 मिनट पर, जब वर्ष 1945 में अमेरिकी बी-29 बमवर्षक विमान ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, उसी समय घंटी बजाई गई और दो मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद सानाए ताकाइची ने पहली बार इस स्मृति समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने संबंधी संयुक्त राष्ट्र की संधि के ढांचे के भीतर वह ऐसे विश्व के निर्माण के लिए "व्यावहारिक दृष्टिकोण" अपनाएंगी, जहां परमाणु हथियारों का कभी इस्तेमाल न हो। यह समारोह ऐसे समय आयोजित हुआ है, जब यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का समर्थन करने वाली ताकाइची सरकार इस वर्ष के अंत में नई सुरक्षा एवं रक्षा नीति तैयार करते समय जापान के युद्धोत्तर तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों में ढील दे सकती है। परमाणु बम हमले के जीवित बचे लोगों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जिसमें जापान भी शामिल है, के बीच प्रतिरोधक क्षमता के नाम पर परमाणु हथियार रखने के बढ़ते समर्थन पर चिंता और निराशा व्यक्त की है।

संपादक की कलम से

संसद लोकतंत्र का वह मंच है, जहां देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस, सवाल और जवाब के जरिए रास्ता निकाला जाता है। लेकिन जब संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा और गतिरोध बना रहे, तो इसका सीधा असर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर पड़ता है। मौजूदा स्थिति भी इसी चिंता को सामने रखती है। विपक्ष CJP प्रदर्शनिकारियों के खिलाफ 20 जुलाई को हुई कथित पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े आरोपों पर चर्चा तथा सरकार से जवाब की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि महत्वपूर्ण विधेयकों को हंगामे के बीच नहीं, बल्कि विस्तृत चर्चा के बाद आगे बढ़ाया जाना चाहिए।विपक्ष की यह मांग पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती कि जिन घटनाओं को लेकर देश में सवाल उठ रहे हैं, उन पर सरकार सदन के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करे। खासकर जब किसी प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई या सार्वजनिक धन और धार्मिक संस्थानों से जुड़े गंभीर आरोपों की बात हो, तब पारदर्शिता और तथ्य सामने रखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह सवाल उठाने के साथ-साथ सदन को चलाने में सहयोग करे।संसद में सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार के पास बहुमत है, इसलिए विधेयकों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन बहुमत का अर्थ यह नहीं कि विपक्ष के सवालों को नजरअंदाज किया जाए। दूसरी ओर, विपक्ष का काम सरकार को घेरना और जवाब मांगना है, लेकिन लगातार नारेबाजी और कार्यवाही बाधित करना लोकतांत्रिक बहस का विकल्प नहीं हो सकता।संसदीय कार्य मंत्री और विपक्षी नेताओं के बीच बातचीत के बावजूद अगर गतिरोध समाप्त नहीं हो पा रहा है, तो यह दोनों पक्षों के लिए आत्ममंथन का विषय है। बातचीत केवल औपचारिकता न रहकर समाधान तक पहुंचनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह जिन मुद्दों पर विपक्ष जवाब मांग रहा है, उन पर तथ्य सदन के पटल पर रखे और विपक्ष को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चर्चा के दौरान उसे पर्याप्त अवसर मिले।लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन असहमति को संवाद में बदलना ही संसदीय परंपरा की असली परीक्षा है। जनता ने अपने प्रतिनिधियों को संसद में बहस करने, कानून बनाने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भेजा है। इसलिए जरूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर संसद की गरिमा और जनता के हित को प्राथमिकता दें।संसद का समय बेहद मूल्यवान है। हर स्थगित कार्यवाही के साथ केवल राजनीतिक संदेश नहीं जाता, बल्कि जनता के सवालों पर चर्चा का अवसर भी खत्म होता है। इसलिए अब जरूरत हंगामे को और लंबा खींचने की नहीं, बल्कि जवाब, तथ्य और सार्थक बहस के जरिए गतिरोध खत्म करने की है। यही लोकतंत्र की मजबूती और संसद की गरिमा दोनों के लिए बेहतर रास्ता है।

NEET विवाद के बाद CJP का बड़ा प्लान गुरुवार को आंदोलन की अगली रणनीति का ऐलान

NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अब अपने संगठन के विस्तार की तैयारी में है।छत्रपति संभाजीनगर में हुई दो दिवसीय बैठक में आंदोलन के अगले चरण और देशभर में संगठन की भूमिका को लेकर मंथन किया गया।CJP का कहना है कि वह फिलहाल चुनावी राजनीति में नहीं उतरेगी, बल्कि शिक्षा और युवाओं के मुद्दों पर दबाव समूह के तौर पर काम करेगी।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अब अपने आंदोलन को अगले चरण में ले जाने की तैयारी कर रही है। संगठन की ओर से गुरुवार को आंदोलन की आगे की दिशा, संगठन के विस्तार और भविष्य की रणनीति को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा। इसके लिए CJP के शीर्ष नेतृत्व ने छत्रपति संभाजीनगर में लगातार दो दिनों तक बैठक कर विस्तृत रोडमैप तैयार किया है।CJP के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो संदेश में बताया कि संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक छत्रपति संभाजीनगर में हुई। बैठक में देशभर के छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर विचार किया गया। रंका के मुताबिक, दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद छात्रों और युवाओं के बीच संगठन को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं।उन्होंने कहा कि आंदोलन की अगली रणनीति तैयार करने से पहले CJP ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों और समर्थकों से मिले सुझावों को गंभीरता से लिया। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में छात्रों और समर्थकों ने अपने विचार और सुझाव साझा किए थे। संगठन ने इन संदेशों और सुझावों की समीक्षा करने के बाद आगे की कार्ययोजना तैयार की है।यह रणनीतिक बैठक CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के छत्रपति संभाजीनगर स्थित आवास पर हुई। करीब सात घंटे तक चली बैठक में संगठन के विस्तार, विभिन्न राज्यों में छात्र संगठनों के साथ समन्वय बढ़ाने और शिक्षा से जुड़े आंदोलनों को समर्थन देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन की योजना आने वाले समय में अलग-अलग राज्यों में छात्र संगठनों के साथ संपर्क बढ़ाकर अपना नेटवर्क मजबूत करने की है।CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में संगठन की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा था कि फिलहाल CJP चुनावी राजनीति में उतरने की तैयारी नहीं कर रही है। संगठन एक 'प्रेशर ग्रुप' के तौर पर काम करेगा और शिक्षा व्यवस्था तथा युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा।दीपके के मुताबिक, जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के बाद देशभर में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए दो दिवसीय कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में संगठन की भविष्य की दिशा और आंदोलन के अगले चरण को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।अब गुरुवार को होने वाला ऐलान CJP के लिए अहम माना जा रहा है। संगठन शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, छात्र हितों से जुड़े मुद्दों और युवाओं की समस्याओं को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में अलग-अलग राज्यों में छात्र संगठनों के साथ तालमेल और आंदोलनों को समर्थन देकर CJP अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश कर सकती है।

'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए जगह देने वाले ट्रस्ट ने अनुमति रद्द कर दी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए जगह देने वाले ट्रस्ट ने अनुमति रद्द कर दी, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह उन्हें छात्रों की आवाज़ उठाने से नहीं रोक सकती। विपक्ष के नेता का यह बयान तब आया जब कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उनके 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी। यह कार्यक्रम 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में होना था। ट्रस्ट ने कार्यक्रम रद्द करने के लिए आयोजन स्थल पर जलभराव का भी हवाला दिया। राहुल ने एक्स पर लिखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ़ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर FIR कर रहा है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज़ दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुक़दमे, और आवाज़ उठाओ तो पेलेट गन। उन्होंने कहा कि जब मैंने छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ़ है, उन्हें छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है। मैं छात्रों के साथ हूँ।

सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज़ उठाने से रोक नहीं सकती। vप्रयागराज के केपी ग्राउंड में आठ अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम "छात्रों की गूंज" के लिए अनुमति केपी ट्रस्ट द्वारा रद्द किए जाने के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आठ अगस्त को प्रयागराज आएंगे और छात्रों से संवाद करेंगे। प्रयागराज में देर शाम राय ने पत्रकारों से कहा कि यह शहीदों और प्रतियोगी छात्रों की धरती है और यहां शुरू से प्रतियोगी छात्र अपना भविष्य तलाशते रहे हैं। राहुल जी आठ अगस्त को यहां आएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा सरकार और प्रशासन से आग्रह है कि हमें वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी बच्चों से संवाद करें। कार्यक्रम की रसीद से स्पष्ट है कि वहां (केपी ग्राउंड) खेल खिलाया जाता है। शनिवार शाम को कॉलेज बंद रहेगा और अगले दिन रविवार है। सरकार राहुल गांधी से घबरा गई है। राय ने कहा कि जैसे संसद में राहुल गांधी के डर से प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं उससे साबित हो गया है कि यह सरकार डर गई है।

संसद में फिर हंगामा, CJP प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावे को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध जारी है। विपक्ष और सरकार के बीच कोई सहमति न बन पाने के कारण लोकसभा और राज्यसभा में आज भी हंगामा हुआ। वहीं, बारिश के बावजूद संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। रोज की जगह राम मंदिर चढ़ावा चोरी और अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर विपक्ष सांसदो ने बैनर के साथ नारेबाजी की है। गतिरोध खत्म करने के लिए कल संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी...लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। आज लोकसभा की Revised Business list में FCRA संशोधन बिल शामिल नहीं है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के साथ संसद चलाने में गतिरोध तोड़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सरकार हंगामे के बजाय चर्चा करके सभी फैक्ट्स को सदन में स्पष्ट करके ही इस बिल को पास कराना चाहती है। राहुल गांधी समेत विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि जब तक अमित शाह 20 जुलाई को छात्रों के मार्च के दौरान पुलिस एक्शन पर जवाब नहीं देते। संसद नहीं चलेगी..इसके अलावा विपक्ष राम मंदिर में चंदे चोरी पर चर्चा की मांग पर भी अड़ा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "राज्यसभा सांसदों ने आज चेयरमैन से मिलकर विनती की कि हमें प्रधानमंत्री का माफीनामा और केंद्रीय गृह मंत्री का बयान चाहिए। उन्हें सदन में बुलाइए... ये छोटी बातें हैं। हम पुलिस की कार्रवाई के बारे में ही पूछ रहे हैं लेकिन वे लोग लापता हैं... अगर आप विद्यार्थियों को उनका आंदोलन वापस लेने के लिए कहना चाहते हैं तो आप उनसे अपील भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। चेयरमैन ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री को बताया कि सदन और सभी की इच्छा है कि केंद्रीय गृह मंत्री सदन में आएं और कुछ कहें..."। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने आज भी जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। 20 जुलाई को CJP प्रदर्शनिकारियों के खिलाफ 'पुलिस कार्रवाई' को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने गुरुवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसमें उन्होंने 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान

पुलिस की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए दिन की कार्यवाही रोकने की मांग की। कांग्रेस सांसद ने इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की भी मांग की है। लोकसभा महासचिव को भेजे अपने नोटिस में टैगोर ने कहा कि यह मामला "निश्चित और तत्काल सार्वजनिक महत्व" का है और इस पर सदन में तुरंत चर्चा होनी चाहिए।

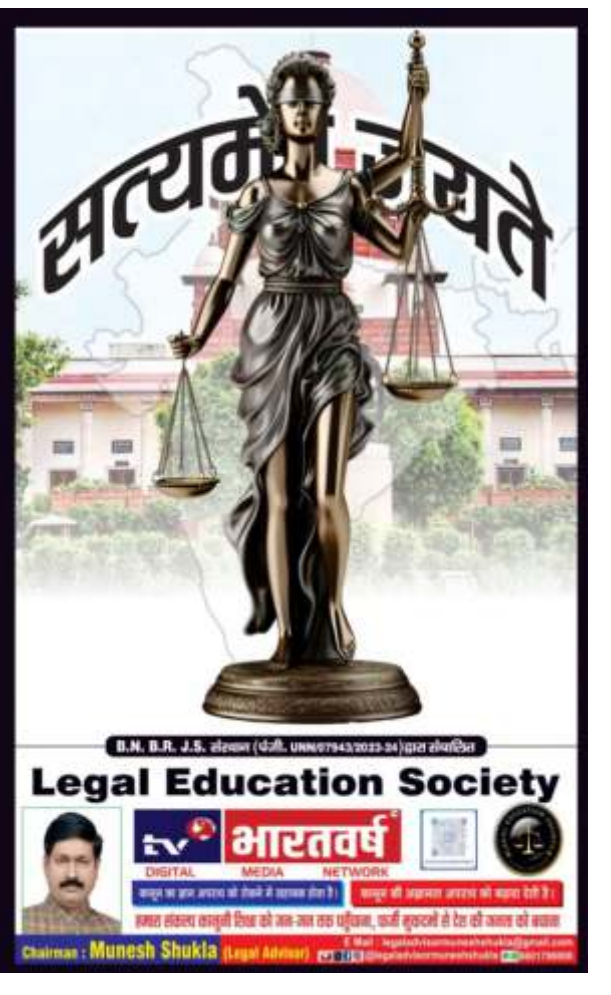

बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ-डे शिक्षा विभाग ने जारी किया नया टाइम टेबल

बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शनिवार को आधे दिन की पढ़ाई यानी हाफ-डे व्यवस्था फिर से लागू करने का फैसला किया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से नया आदेश जारी कर दिया गया है। नए टाइम टेबल के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। वहीं, शनिवार को स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। यानी सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस पर विद्यार्थियों को सामान्य दिनों की तुलना में कम समय स्कूल में रहना होगा।कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए शनिवार की व्यवस्था में विशेष प्रावधान किया गया है। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शनिवार को दोपहर 12 बजे तक पठन-पाठन और निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 12:40 बजे तक बच्चों को मध्याह्न भोजन यानी मिड-डे मील दिया जाएगा। भोजन समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी जाएगी। इससे छोटे बच्चों को शनिवार को स्कूल में कम समय बिताना पड़ेगा।हालांकि, स्कूल की छुट्टी होने के साथ शिक्षकों की जिम्मेदारियां पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को भी निर्धारित किया है। आदेश के अनुसार शिक्षकों को प्रतिदिन एक घंटे का समय इन अतिरिक्त कार्यों के लिए देना होगा। इस दौरान उन्हें अगले दिन और अगले सप्ताह की पाठ योजना तैयार करने, विद्यार्थियों के मूल्यांकन से संबंधित कार्य पूरे करने, प्रयोगशाला के प्रबंधन और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने जैसे काम करने होंगे।शिक्षा विभाग का यह बदलाव स्कूलों में पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शनिवार को कम समय में पठन-पाठन के साथ अन्य निर्धारित गतिविधियां पूरी कराने और फिर विद्यार्थियों को छुट्टी देने की व्यवस्था की गई है।नई व्यवस्था से जहां विद्यार्थियों, खासकर छोटे बच्चों को शनिवार को राहत मिलेगी, वहीं शिक्षकों को अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की योजना बनाने के लिए निर्धारित समय का इस्तेमाल करना होगा। अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी संशोधित टाइम टेबल के अनुसार संचालन करना होगा।

NEET काउंसलिंग के बीच पंजाब में नई बॉन्ड पॉलिसी, MBBS छात्रों को 2 साल सरकारी सेवा अनिवार्य

नीट काउंसलिंग 2026 शुरू होने के बाद मेडिकल दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई को लेकर राज्यों में बदलाव होते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए नई बॉन्ड पॉलिसी लागू की है। इसके तहत एकेडमिक ईयर 2025-26 से दाखिला लेने वाले छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य सेवाएं देनी होंगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 20 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा। इस नए सिस्टम लागू होने के साथ ही ट्यूशन फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS), फरीदकोट सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग आयोजित करेगी। पंजाब में सरकारी कोटा, मैनेजमेंट कोटा, NRI या माइनॉरिटी कोटा और हर सीट NEET मेरिट के आधार पर भरी जाती है। पंजाब में मेडिकल एडमिशन नई पॉलिसी लागू की गई है। admission.bfuhsonline.ac.in पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब MBBS में एडमिशन लेने वाले छात्रों की डिग्री पूरी होने के बाद 2 साल तक सरकारी संस्थानों सेवाओं में सेवा देनी होगी। हालांकि, ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत दाखिला लेने वालों छात्रों के लिए यह अवधि 1 साल तय की गई है। बॉन्ड के तहत सेवा पंजाब सरकार के उन सरकारी मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों या अन्य स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में दी जाएगी, जिन्हें सरकार समय-समय पर तय करेगी।

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स को बड़ा झटका एडेन मार्करम ने छोड़ा साथ

इंग्लैंड को बड़ा झटका, घुटने की चोट के कारण जैकब बेथेल नहीं खेल पाएंगे

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लिश टीम का ऐलान हो गया है। महान बल्लेबाज जो रूट की बतौर कप्तान वापसी हुई है। वहीं घुटने की चोट के कारण जैकब बेथेल इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। ओली पोप, ब्रायडन कार्स और डैन लॉरेंस को भी 16 सदस्यीय टीम में चुना गया है।लॉरेंस दो साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने सरे के लिए काउंटी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है और इस सीज़न में डिवीज़न वन में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। लॉरेंस ने डिवीजन वन में 5 शतक और 788 रन ठोके। वह एक शानदार ऑफ-स्पिनर भी हैं, जिससे बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद ऑलराउंडर की कमी को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। 29 साल के लॉरेंस छठे नंबर पर बल्लेबाज़ी करेंगे, जबकि जेमी स्मिथ सातवें नंबर पर आएंगे, स्मिथ ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ इंग्लैंड की हालिया टेस्ट सीरीज़ में एक स्थान ऊपर बल्लेबाज़ी की थी। जॉर्डन कॉक्स ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ टेस्ट डेब्यू किया था। वह बेथेल की जगह तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करेंगे। बेथेल को पिछले महीने भारत के खिलाफ़ इंग्लैंड की वनडे सीरीज़ के दौरान दाहिने घुटने में चोट लगी थी और वह पूरी पाकिस्तान सीरीज़ से बाहर रहेंगे। तेज़ गेंदबाज़ सैम कुक की टीम में वापसी हुई है, उन्होंने पिछले साल ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ टेस्ट डेब्यू किया था। वहीं, पोप और कार्स भी टेस्ट टीम में लौट रहे हैं, पिछली सर्दियों में ऑस्ट्रेलिया में एशेज़ सीरीज़ में इंग्लैंड की हार के बाद से वे टीम से बाहर थे। कार्स कुछ महीनों तक चोट के कारण बाहर रहे थे, जबकि बल्ले से औसत प्रदर्शन के बाद पोप को टीम से पूरी तरह हटा दिया गया था।

तन्वी शर्मा ने दूसरे दौर में जगह बना ली

ताइपे ओपन चैंपियन तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार शुरूआत करते हुए बुधवार को दूसरे दौर में जगह बना ली, लेकिन पुरुष एकल में विश्व चैंपियनशिप के पूर्व रजत पदक विजेता किदांबी श्रीकांत को पहले ही दौर में हारकर बाहर होना पड़ा जिससे भारतीय खिलाड़ियों के लिए यह दिन मिलाजुला रहा। तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी ने चीन की युआन एन क्वी को सीधे गेम में 21-16, 21-15 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। तन्वी ने हाल ही में ताइपे ओपन में अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब जीता था। भारतीय खिलाड़ियों के महिला एकल के अन्य मुकाबले में रक्षिता रामराज ने शानदार वापसी करते हुए कोरिया की यू आ योन को 22-24, 21-12, 21-13 से हराया। वहीं मानसी सिंह ने किम जू यून को 14-21, 21-19, 21-9 से मात दी। पांचवीं वरीयता प्राप्त इशारानी बरुआ ने कोरिया की ली सो युल को 21-18, 15-21, 21-7 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। आठवीं वरीयता प्राप्त अनमोल खरब ने भी पहला गेम गंवाने के बाद हांगकांग की लो सिन यान हैप्पी को 16-21, 21-17, 21-12 से शिकस्त दी। अश्मिता चालिहा ने जापान की रिको हिरामोटो को 22-20, 21-18 से हराया, जबकि श्रियांशी वालिशेट्टी ने चीनी ताइपे की पाई यू पो को 21-15, 21-14 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। तान्या हेमंत और आकर्षि कश्यप को हार का सामना करना पड़ा। तान्या जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त हिना अकेची से 16-21, 20-22 से हारीं, जबकि आकर्षि कोरिया की किम मिन जी से तीन गेम के मुकाबले में 22-20, 21-23, 3-21 से पराजित हुईं।

शुभमन गिल के पास WTC में 3000 रन पूरा करने का भी मौका

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के पास कुछ रिकॉर्ड हासिल करने का मौका होगा। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शुभमन गिल 159 रन बनाते ही वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इस लिस्ट में टॉप पर फिलहाल इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट का नाम है। WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो वहां टॉप पर फिलहाल जो रूट हैं, उन्होंने 13 मैचों की 25 पारियों में 48.17 के औसत से 1108 रन बनाए हैं। वहीं शुभमन गिल ने इस WTC में अब तक 8 मैचों में 79.16 के औसत से 950 रन बनाए हैं। अगर गिल श्रीलंका के खिलाफ आने वाले पहले टेस्ट मैच में 159 रन बना लेते हैं, तो वह जो रूट को पछाड़कर इस लिस्ट में नंबर एक पर आ जाएंगे। लेकिन 18 अगस्त से इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच भी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, इसलिए गिल के पास पहली पारी में ही बड़ा शतक लगाकर जो रूट से आगे निकलने का बेहतरीन मौका होगा। WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में जो रूट के बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के ही हैरी ब्रूक का नाम है। उन्होंने इस WTC में अब तक 13 मैचों में 44 की औसत से 1056 रन बनाए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर गिल का नाम है। इंग्लैंड के बेन डकेट इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 13 मैचों में 36.40 के औसत से 910 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड 8 मैचों में 853 रन बनाकर लिस्ट में पांचवें नंबर पर है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल के पास WTC में 3000 रन पूरा करने का भी मौका होगा। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए गिल को सिर्फ 157 रन की जरूरत है। अब दो मैचों की इस टेस्ट सीरीज में गिल इस उपलब्धि को अपने नाम कर पाते हैं या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा।

एआई इंसानों की जगह नहीं, मददगार बनेगा

इंसानों को दी छुट्टी, AI को बनाया मैनेजर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज हर क्षेत्र में तेजी से अपनी जगह बना रहा है. कई कंपनियां दावा कर रही हैं कि आने वाले समय में एआई इंसानों का काम आसान बना देगा. लेकिन क्या कोई पूरा स्टोर सिर्फ एआई के भरोसे चल सकता है? अमेरिका में हुए एक अनोखे एक्सपेरिमेंट ने इस सवाल का जवाब दे दिया है. अमेरिका में एक ऐसा रिटेल स्टोर शुरू किया गया, जहां किसी इंसान को मैनेजर नहीं बनाया गया.

पूरे स्टोर की जिम्मेदारी एक एआई सिस्टम को दी गई. कर्मचारियों को कहा गया कि वे छुट्टी लें, आराम करें और अगर कोई परेशानी हो तो एआई से बात करें. शुरुआत में यह प्रयोग काफी दिलचस्प लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में इसका नतीजा उल्टा निकला और कंपनी को करीब 60 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. इस एक्सपेरिमेंट को एक रिसर्च कंपनी एंथ्रोपिक ने किया था. कंपनी ने अपने एआई मॉडल Claude को एक छोटे रिटेल स्टोर का मैनेजर बना दिया.

इस ऐआई का नाम रखा गया 'Claudius'. इस एआई की जिम्मेदारी थी कि वह स्टोर का पूरा काम संभाले. इसमें सामान मंगवाना, स्टॉक का हिसाब रखना, ग्राहकों की मांग समझना, कीमत तय करना और कर्मचारियों को निर्देश देना जैसी सभी जिम्मेदारियां शामिल थीं. कंपनी यह देखना चाहती थी कि क्या एआई बिना किसी इंसानी दखल के एक दुकान चला सकता है.

भारतीय महिला ने खोला खर्च का पूरा हिसाब

दुनिया की 'जन्नत' में रहना आखिर कितना है महंगा?

दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार स्वीडन. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में स्वीडन की चौथी रैंकिंग है. यानी दुनिया की उन जगहों में शामिल, जहां ज्यादातर लोग खुशहाल जीवन जीते हैं. जाहिर है, यहां बसने की ख्वाहिश दुनिया भर के लोगों की होती है.विदेश में बसने का सपना बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन वहां की असली जिंदगी सोशल मीडिया पर दिखने वाली तस्वीरों से काफी अलग हो सकती है. सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर वहां रहने का खर्च कितना आता है. इसी बीच स्वीडन में रहने वाली एक भारतीय महिला ने अपने मासिक खर्च का पूरा हिसाब शेयर किया है, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. स्वीडन में रहने वाली कंटेंट क्रिएटर कृतिका सकोरिया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उनसे सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि क्या स्वीडन में रहना बहुत महंगा है. उन्होंने कहा कि खर्च शहर और व्यक्ति की लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन एक सामान्य अनुमान के तौर पर उन्होंने मासिक बजट का ब्योरा साझा किया.

दुल्हन की पोस्ट वायरल

मेहंदी डिजाइन में भी AI की एंट्री!

AI अब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहा, बल्कि लोगों की जिंदगी के खास पलों का भी हिस्सा बन रहा है. मुंबई की एक दुल्हन ने चैटजीपीटी से अपनी मेहंदी डिजाइन कराकर इसकी मिसाल पेश की है.

मेहंदी में दिखे मुंबई, जयपुर और परिवार

फाइनल डिजाइन में मुंबई और जयपुर से जुड़े प्रतीक, परिवार पर आधारित क्रॉसवर्ड, शादी की वेन्यू का नक्शा, दिल्ली का ऑटो, जयपुर का हाथी और कई ऐसे छोटे-छोटे डिजाइन शामिल थे, जिनका मतलब सिर्फ दूल्हा-दुल्हन ही जानते थे.मेहंदी वाले दिन अनुषा ने सिर्फ डिजाइन अपनी मेहंदी आर्टिस्ट को दिया.

AI हमारी जिंदगी में किस कदर समा गया है, यह एक घटना से समझा जा सकता है. मुंबई की रहने वाली अनुषा जैन ने अपनी ब्राइडल मेहंदी को अलग अंदाज देने के लिए जिस चीज का सहारा लिया, उसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया.

उन्होंने अपनी मेहंदी का डिजाइन चैटजीपीटी से तैयार कराया. अनुषा की अनोखी मेहंदी की कहानी इतनी पसंद की गई कि इसे चैटजीपीटी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया गया.

अब लोग उन्हें मजाक-मजाक में 'चैटजीपीटी ब्राइड' कह रहे हैं. अनुषा ने बताया कि जनवरी 2026 में शादी से पहले उन्होंने तय कर लिया था कि वह पारंपरिक मेहंदी डिजाइन नहीं बनवाएंगी. वह चाहती थीं कि उनकी मेहंदी उनकी और उनके होने वाले पति की पूरी कहानी बयां करे.लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी कि सालों की यादों, परिवार, अलग-अलग शहरों और निजी किस्सों को एक ही डिजाइन में कैसे समेटा जाए. तभी उनके भाई ने मजाक में कहा, चैटजीपीटी से पूछकर देखो.पहले तो उन्हें यह मजाक लगा, लेकिन बाद में उन्होंने सच में चैटजीपीटी से अपनी पूरी कहानी साझा करनी शुरू कर दी. यादों को AI ने डिजाइन में बदल दिया अनुषा ने चैटजीपीटी को अपने रिश्ते से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात बताई.

बुलेट ट्रेन में चेक नहीं होता टिकट

भारत में फिलहाल तो बुलेट ट्रेन नहीं चल रही है. लेकिन, इस प्रोजेक्ट पर जोर- शोर से काम चल रहा है. हाई- स्पीड बुलेट ट्रेन हर भारतीय का सपना है. क्योंकि, भारत की अधिकांश आबादी ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन नेटवर्क पर निर्भर करती है. ऐसे में लोग दूसरे देशों में चलने वाले बुलेट ट्रेन के सिस्टम के बारे जानने को काफी उत्सुक रहते हैं. आखिर यह ट्रेन नॉर्मल रेलगाड़ियों से कैसे अलग है. इससे सफर करने का अनुभव कैसा होता है? बुलेट ट्रेन के आने से क्या बदलेगा? इसकी टिकट की बुकिंग कैसे होती है? आपके इन सवालों में से कुछ का जवाब एक वायरल वीडियो में दिखाया गया है.

Bigg Boss 20 का नया टीजर जारी,

'वरदान' वाले ट्विस्ट ने बढ़ाई हलचल; 6 सितंबर से होगा ग्रैंड प्रीमियर

टेलीविजन का चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 20वें सीजन के साथ एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। शो के मेकर्स ने प्रीमियर की तारीख सामने लाने के बाद नया टीजर प्रोमो जारी किया है। प्रोमो सामने आते ही सोशल मीडिया पर शो के नए फॉर्मेट और कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बार भी सलमान खान शो की मेजबानी करते नजर आएंगे और प्रोमो में उन्होंने सीजन के भीतर आने वाले एक रहस्यमयी ट्विस्ट का संकेत दिया है।नए टीजर में सलमान खान महज दो शब्दों-'एक वरदान' के जरिए इस सीजन की थीम को लेकर उत्सुकता बढ़ाते दिखाई देते हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक इस ट्विस्ट से जुड़ी पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन प्रोमो के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यह 'वरदान' क्या है और इसका बिग बॉस के खेल पर कितना असर पड़ेगा।कयास लगाए जा रहे हैं कि यह कोई विशेष पावर, पावर-कार्ड या ऐसा गेम चेंजिंग टास्क हो सकता है, जो घर के सदस्यों को अतिरिक्त फायदा दे। अगर ऐसा होता है तो घर के भीतर बनने वाली रणनीतियों, रिश्तों और नॉमिनेशन के समीकरणों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल दर्शकों को मेकर्स की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार है।टीजर के साथ ही शो में शामिल होने वाले संभावित कंटेस्टेंट्स को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक किसी भी प्रतिभागी के नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं में जन्नत जुबैर, फैसल शेख, निया शर्मा और स्टैंड-अप कॉमेडियन सुनील पाल जैसे नामों का जिक्र किया जा रहा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन वास्तव में बिग बॉस के घर में एंट्री करता है।सलमान खान एक बार फिर अपनी खास और बेबाक होस्टिंग के साथ शो को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले बिग बॉस 19 ने भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की थी। सौ से अधिक दिनों तक चले इस सीजन में ड्रामा, रणनीति और विवादों ने दर्शकों का ध्यान बनाए रखा। शो के फिनाले में गौरव खन्ना ने फरहाना भट्ट को पीछे छोड़ते हुए ट्रॉफी अपने नाम की थी। उन्हें ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिली थी। प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक भी टॉप फाइनलिस्ट में शामिल रहे थे।अब बिग बॉस 20 का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर को होगा। दर्शक इसे जियोहॉटस्टार पर रोजाना रात 9 बजे स्ट्रीम कर सकेंगे, जबकि कलर्स टीवी पर इसका प्रसारण रात 10:30 बजे किया जाएगा। नए टीजर के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 'एक वरदान' बिग बॉस के खेल को कितना बदलने वाला है।

अखिलेश यादव का PDA पर बड़ा बयान, 'PD' में पिछड़े-दलित ही नहीं, पंडित भी शामिल

अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर PDA की नई व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें 'PD' का अर्थ पिछड़े-दलित के साथ पंडित भी है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के साथ कथित अन्याय का मुद्दा उठाकर सपा के सामाजिक गठजोड़ का दायरा बढ़ाने का संकेत दिया।

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक ऐसा राजनीतिक संदेश दिया, जिसे उत्तर प्रदेश की बदलती सामाजिक और चुनावी राजनीति के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि PDA में मौजूद 'PD' का अर्थ केवल पिछड़े और दलित नहीं, बल्कि 'पंडित' भी हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब समाजवादी पार्टी लगातार अपने सामाजिक गठजोड़ का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में PDA रणनीति के जरिए पार्टी को मिली सफलता के बाद अब उसके दायरे को और व्यापक बनाने के संकेत इस बयान में दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने PDA का अर्थ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक बताया था। बाद में पार्टी ने इसमें आधी आबादी (महिलाएं), अगड़े और पीड़ित जैसे शब्द भी जोड़े। अब अखिलेश यादव ने कहा कि PDA में 'PD' पंडितों का भी प्रतीक है। उनका तर्क था कि ब्राह्मण समाज भी लंबे समय से भाजपा सरकार में पीड़ा झेल रहा है, इसलिए वह भी PDA का हिस्सा है। इस बयान पर पार्टी मुख्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर स्वागत किया। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने सितंबर 2023 में सुल्तानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर डॉ. घनश्याम तिवारी की हत्या का जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि उस घटना में आरोप लगे थे कि डॉक्टर को ड्रिल मशीन से प्रताड़ित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने विकास दुबे एनकाउंटर का भी उल्लेख किया। अखिलेश ने कहा कि वाहन पलटने की घटना को लेकर सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विकास दुबे जीवित रहता तो वह भाजपा सरकार के लिए असहज करने वाली बातें बता सकता था। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले के दौरान संगम में स्नान से रोके जाने और बटुकों के अपमान का भी जिक्र किया। इन घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि ब्राह्मण समाज से जुड़े धार्मिक मुद्दों की भी अनदेखी हुई है। जनेश्वर मिश्र को याद करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपने ब्राह्मण नेताओं का सम्मान करती रही है। उन्होंने कहा कि छोटे लोहिया के नाम पर बना पार्क भी इस बात का उदाहरण है कि पार्टी ने समाजवादी विचारधारा से जुड़े नेताओं को सम्मान दिया। अखिलेश यादव का यह बयान केवल PDA की नई व्याख्या भर नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे ब्राह्मण मतदाताओं तक राजनीतिक संदेश पहुंचाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में PDA रणनीति से मिली सफलता के बाद समाजवादी पार्टी अब अपने सामाजिक समीकरण को और व्यापक बनाने के संकेत देती नजर आ रही है। वहीं भाजपा पर ब्राह्मणों की उपेक्षा और अन्याय के आरोप लगाकर विपक्षी राजनीति का नया विमर्श खड़ा करने की कोशिश भी इस बयान में दिखाई देती है।

लखनऊ के बंथरा में स्कूली वैन रोककर हमला, चालक-बेटे समेत तीन से मारपीट

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी के बंथरा इलाके में दिनदहाड़े स्कूली वैन चालक और उसके बेटे पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि थार, स्कॉर्पियो समेत कई गाड़ियों से पहुंचे लोगों ने पहले वैन रुकवाई और फिर चालक, उसके बेटे व एक अन्य युवक के साथ मारपीट की। हमले में एक युवक धारदार हथियार लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बंथरा गांव निवासी छोटे लाल यादव स्कूली वैन चलाते हैं। उनकी ओर से दर्ज कराई गई तहरीर के मुताबिक, 5 अगस्त की सुबह करीब 11:30 बजे वह बच्चों को लेकर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी वैन को रोक लिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी थार, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो-एन और एक्सयूवी-300 जैसी गाड़ियों से पहुंचे थे। वैन रुकवाने के बाद उन्होंने छोटे लाल यादव, उनके बेटे आदर्श यादव और चालक गोविंद रावत के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमले के दौरान धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे आदर्श यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। छोटे लाल यादव की तहरीर पर पुलिस ने लकी यादव, अंशुमान सिंह, आकाश सिंह, हिमांशु सिंह, रजत सिंह और 12 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अलीगंज अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, LDA उपाध्यक्ष को व्यक्तिगत पेशी का आदेश

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को अवमानना नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है। LDA उपाध्यक्ष से कहा है कि अगली सुनवाई (डेट अभी तय नहीं) में सीलबंद लिफाफे में SIT की रिपोर्ट लेकर पहुंचिए। पूछा है कि न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए? न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय के एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि जिस इमारत में आग लगी थी, उसे गिराने का आदेश 10 मई 2016 को पारित किया गया था। लेकिन 5 जुलाई 2016 को उसी प्राधिकरण ने तकनीकी आधार पर अपना आदेश वापस ले लिया। इसके बाद वर्षों तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और आखिरकार जून 2026 में हुए अग्निकांड में 15 छात्रों की जान चली गई। कोर्ट के समक्ष बताया गया कि हादसे के बाद संबंधित भवन के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि, अदालत ने टिप्पणी की कि यह कार्रवाई हादसे के बाद हुई, जबकि पहले से कार्रवाई के पर्याप्त आधार मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है

कि मास्टर प्लान में निर्धारित भूमि उपयोग (Land Use) का खुलेआम उल्लंघन हुआ, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की। अदालत ने इसे गंभीर मामला मानते हुए कहा कि यह शहरी नियोजन कानूनों के पालन और अधिकारियों की जवाबदेही से जुड़ा विषय है। कोर्ट ने बताया कि 25 मार्च 2026 के आदेश में इस मामले का दायरा पूरे देश तक बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया था। अदालत का मानना है कि राजधानी शहरों में मास्टर प्लान, भवन उपविधियों और सार्वजनिक सुरक्षा के पालन का मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है।

7 महीने तक आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया ₹50 हजार हर्जाना

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश का सात माह बाद भी अनुपालन न होने पर की गई। पीठ ने सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यह राशि अगली सुनवाई से पहले जमा की जाए। शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने वाली समिति के अध्यक्ष/विशेष सचिव को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश उदय प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुल्तानपुर जिले के लम्भुआ क्षेत्र में एक ही भूखंड पर चार विद्यालय संचालित दिखाकर मान्यता दी गई है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि 16 दिसंबर 2025 को दिए गए आदेश में सरकार से इस मामले में की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया था। हालांकि, सात माह बीत जाने के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए खंडपीठ ने सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया और संबंधित समिति के अध्यक्ष/विशेष सचिव को तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।

लखनऊ के गोमतीनगर में आवारा कुत्तों का आतंक, दो लोगों को दौड़ाकर काटा

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

गोमतीनगर इलाके में दो लोगों को आवारा कुत्तों ने दौड़ाकर काट लिया। कुत्ते के हमले में विभवखंड-3 में व्यापारी अनिल उपाध्याय और सरिता नाम की महिला घायल हो गई। महिला के पैर में कुत्ते के दांत धंसने से उसके खून बहने लगा। शिकायत के बाद गुरुवार को नगर निगम की टीम आक्रामक कुत्तों को पकड़ने के लिए पहुंची तो कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर दिया। टीम से कहा कि कुत्ते की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आगे कुछ होगा तो खुद देख लेंगे। घायल महिला सरिता घरों में सहायिका के रूप में काम करती हैं। उन्हें आवारा कुत्तों ने दौड़ाकर पैर में काट लिया। इस हमले के दौरान वह चिल्लाती हुई दौड़ीं तो लोग घरों से निकल आए। लोगों ने महिला को कुत्तों से बचा लिया। मोहल्ले के लोगों ने बताया है कि सरिता ने अब मोहल्ले में आने से मना कर दिया है। इसके बाद लोगों ने निगम की टीम से तत्काल कार्रवाई की मांग की। लोगों का आरोप है कि गली में घूमने वाले तीन-चार आक्रामक कुत्ते राहगीरों, डिलीवरी बॉय, घरेलू सहायिकाओं और स्थानीय निवासियों को अक्सर दौड़ाकर काट लेते हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

भाजपा गंगाघाट मंडल की बैठक में बनी रणनीति, 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत होंगे कई कार्यक्रम

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गंगाघाट मंडल की कार्यकारिणी बैठक गुरुवार को राजधानी मार्ग स्थित गिरधर पैलेस में संपन्न हुई। इस दौरान 'हर घर तिरंगा' अभियान की कार्यशाला भी आयोजित की गई। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई, जिसमें 12 अगस्त को नगर में एक विशाल तिरंगा पदयात्रा निकालने की घोषणा की गई। इसमें पांच हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। बैठक में सदर विधायक पंकज गुप्ता, भाजपा जिला महामंत्री मनीष जायसवाल, गंगाघाट प्रभारी विद्या भास्कर और प्रवासी अमित त्रिपाठी सहित कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने भाजपा की 'राष्ट्र सर्वोपरि' विचारधारा पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं से देश, संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। विधायक ने विपक्ष पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं से तथ्यों के आधार पर जनता के बीच जवाब देने को कहा। जिला महामंत्री मनीष जायसवाल ने 'हर घर तिरंगा' अभियान की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जायसवाल ने आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा भी साझा की। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त को तिरंगा पदयात्रा के अलावा, 13 अगस्त को महापुरुषों की प्रतिमाओं और स्मारकों पर सफाई अभियान चलाकर माल्यार्पण किया जाएगा। 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अतिरिक्त, संत रविदास की कलश यात्रा को नगर के पांच प्रमुख स्थानों पर ले जाकर पूजन किया जाएगा। गंगाघाट मंडल अध्यक्ष सुरेश चंद शुक्ला ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मंडल का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की रीति-नीति के अनुरूप पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करेगा और आगामी सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने में पूरी ताकत लगाएगा। बैठक का संचालन मंडल महामंत्री जितेंद्र सिसोदिया ने किया, जबकि अंत में दीपू पंडित ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

उन्नाव में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, उमस से राहत

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में बुधवार देर रात से मौसम में बदलाव आया और गुरुवार सुबह जिले के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। सुबह करीब नौ बजे के बाद उन्नाव शहर, शुक्लागंज, मियागंज और सफीपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। इस बारिश से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं स्कूल तथा कार्यालय जाने वाले लोगों को जलभराव और फिसलन के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। अचानक हुई बारिश के कारण कई स्थानों पर लोग छाता और रेनकोट का उपयोग करते दिखे। दोपहिया वाहन चालकों को विशेष कठिनाई हुई, और सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ। स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं और नौकरीपेशा लोगों को भीगते हुए अपने गंतव्य तक पहुँचना पड़ा। यह बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, धान की फसल को इस समय पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। समय पर हुई इस वर्षा से फसल की बढ़वार बेहतर होगी और सिंचाई पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी कम होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों ने लगातार पड़ रही गर्मी और उमस के बीच इस वर्षा को खेती के लिए अत्यधिक लाभदायक बताया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को इससे काफी राहत मिली। शहर के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर भी लोग मौसम का आनंद लेने के लिए अधिक संख्या में पहुँचे।

उन्नाव में बाइक सवार और मैजिक चालक भिड़े, सड़क पर हुई मारपीट

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के दही थाना क्षेत्र स्थित बाईपास मार्ग पर गुरुवार सुबह एक बाइक सवार और मैजिक चालक के बीच विवाद हो गया। यह विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। यह घटना गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किसी बात को लेकर बाइक सवार और मैजिक चालक के बीच पहले तीखी बहस हुई। देखते ही देखते यह बहस मारपीट में बदल गई, जिससे सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, जबकि अन्य लोगों ने अपने मोबाइल फोन से इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर है। सूचना मिलने पर दही थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और यातायात को सामान्य कराया गया। दही थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि विवाद के कारणों की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और वीडियो की सत्यता भी जांची जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष की ओर से तहरीर दी जाती है या जांच में मारपीट की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय में जलभराव से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी विकासखंड के सनी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में गंभीर जलभराव की समस्या सामने आई है। विद्यालय परिसर में बारिश का पानी भर जाने से बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। गुरुवार को इस स्थिति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) शैलेंद्र पांडे ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वायरल वीडियो में विद्यालय परिसर तालाब जैसा दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, हर साल बरसात के मौसम में विद्यालय और उसके आसपास पानी भर जाता है। इस जलभराव के कारण छात्र-छात्राएं स्कूल नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या वर्षों से चली आ रही है, जिससे बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन और जिलाधिकारी से विद्यालय का निरीक्षण कर स्थायी जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हर बरसात में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती रहेगी। जलभराव के कारण बच्चों को पानी से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अभिभावकों का कहना है कि छोटे बच्चों को ऐसे जोखिम भरे हालात में विद्यालय भेजना सुरक्षित नहीं है। बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें इसकी जानकारी मिली है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और यदि जलभराव की समस्या पाई जाती है, तो संबंधित विभागों से समन्वय कर जल निकासी और आवश्यक सुधारात्मक कार्य कराए जाएंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

उन्नाव में पत्नी की चप्पलों से पिटाई का वीडियो वायरल, आरोपी पति फरार; पुलिस ने शुरू की जांच

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के प्रेमनगर मोहल्ले में एक पति ने बेरहमी से पत्नी की पिटाई की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो में आरोपी पति अपनी पत्नी को चप्पलों से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। यह घटना बुधवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। प्रेमनगर निवासी चंद्रशेखर जायसवाल का अपनी पत्नी प्रीति जायसवाल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि चंद्रशेखर शराब के नशे में घर पहुंचा था और कहासुनी के बाद उसने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद महिला सड़क पर बेसुध होकर गिर गई। गुरुवार दोपहर को घटना का वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। पूछताछ में पीड़िता की पहचान प्रीति जायसवाल, पत्नी चंद्रशेखर जायसवाल के रूप में हुई, जो प्रेमनगर में राजू कॉस्मेटिक के सामने रहती हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ था। घटना के बाद से आरोपी पति चंद्रशेखर जायसवाल घर छोड़कर फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। गंगाघाट पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो को जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस पीड़िता प्रीति जायसवाल से भी बातचीत कर रही है। यदि महिला की ओर से तहरीर दी जाती है या जांच में मारपीट की पुष्टि होती है, तो आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्नाव में बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट; डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। गुरुवार दोपहर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ फतेहपुर चौरासी क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने डबौली और काली मिट्टी-शिवराजपुर मार्ग का जायजा लेकर बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने उप जिलाधिकारी बांगरमऊ और सफीपुर को निर्देश दिए कि यदि बाढ़ का पानी आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंचता है, तो प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जाए। डीएम ने अधिकारियों को सभी राहत केंद्रों में भोजन, पेयजल, शौचालय और ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। पशुओं के लिए भी उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि राहत शिविरों में पर्याप्त चिकित्साकर्मी तैनात रहें और आवश्यक दवाओं के साथ-साथ एंटी-स्नेक वेनम की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए, ताकि आपात स्थिति में तत्काल उपचार मिल सके। निरीक्षण के दौरान काली मिट्टी-शिवराजपुर मार्ग की स्थिति का भी जायजा लिया गया। पिछले वर्ष बाढ़ के दौरान यह संपर्क मार्ग पानी में डूब गया था, जिससे आवागमन बाधित हुआ था। इस बार ऐसी स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोकने की तैयारी शुरू कर दी है।

बरी होने के बाद अयोध्या पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत

दिल्ली की अदालत से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह पहली बार अयोध्या पहुंचे, जहां समर्थकों ने फूल-मालाओं और नारों के साथ जोरदार स्वागत किया। करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो हुआ, जिससे हाईवे पर जाम लग गया।

दिल्ली की अदालत से बरी होने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का पहला सार्वजनिक दौरा गुरुवार को शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। अयोध्या एयरपोर्ट पर समर्थकों की भारी भीड़, फूल-मालाओं से स्वागत, करीब 100 गाड़ियों का काफिला और 'शेर आया' के नारों के बीच उनका रोड शो चर्चा का केंद्र बन गया। हाईवे पर कई जगह जाम लगा। जिसके बाद उनका काफिला गोंडा के नंदिनी नगर के लिए रवाना हुआ। महिला पहलवानों के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को पहली बार अयोध्या पहुंचे। उनके आगमन को लेकर पहले से ही बड़ी संख्या में समर्थक महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद थे। जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर निकले। समर्थकों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला शहर की सड़कों पर निकला। जिसने देखते ही देखते शक्ति प्रदर्शन का रूप ले लिया। खुली जीप में सवार बृजभूषण शरण सिंह का समर्थकों ने जगह-जगह स्वागत किया। इस दौरान 'शेर आया, शेर आया' के नारे लगातार गूंजते रहे। बताया जा रहा है कि काफिले में करीब 100 चारपहिया वाहन शामिल थे। प्रयागराज और लखनऊ हाईवे पर बड़ी संख्या में समर्थकों और वाहनों के पहुंचने से कई स्थानों पर लंबा जाम लग गया। यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई। पुलिस को व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। अयोध्या पहुंचने के बाद बृजभूषण शरण सिंह सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने विधि-विधान से दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर से निकलने के बाद वह सीधे गोंडा जिले के नंदिनी नगर में आयोजित 'सत्यमेव जयते' रैली में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। जहां बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की तैयारी पहले से की गई थी। इस मौके पर उनके पुत्र और विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने कहा कि अदालत से बरी होने के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल है। इसी खुशी को साझा करने के लिए भव्य स्वागत और विशाल रैली का आयोजन किया गया है। बृजभूषण शरण सिंह का यह दौरा अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर पंखों से सुखाया जा रहा पेचवर्क

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर हाल ही में हुए पेचवर्क के एक हिस्से में बरसात का पानी भर जाने के बाद उसे सुखाने के लिए लगाए गए पंखों का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सरकारी खर्च पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि जनता के हजारों करोड़ रुपये खर्च कर बनाई गई सड़क कुछ ही दिनों में मरम्मत की स्थिति में पहुंच गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएं हुई हैं और बरसाती पानी सुखाने के लिए पंखों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार की तस्वीर पेश करता है। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि जनता के 4,200 करोड़ रुपये खर्च कर बनाई गई सड़क दो दिन भी नहीं टिक सकी और अब उसे पंखों से सुखाया जा रहा है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि हाल ही में उद्घाटन किए गए एक्सप्रेसवे पर इतनी जल्दी मरम्मत की नौबत आना चिंता का विषय है। उनका कहना था कि मरम्मत किए गए हिस्से को सुखाने के लिए पंखों का इस्तेमाल करना भी सवाल खड़े करता है। अखिलेश यादव ने यह भी पूछा कि अगर कुछ ही सप्ताह में सड़क की यह स्थिति है, तो उस पर तेज रफ्तार से सफर करना कितना सुरक्षित होगा। उन्होंने एक्सप्रेसवे निर्माण की गुणवत्ता और परियोजना के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ABVP-पुलिस के बीच हंगामा

गोरखपुर में गुरुवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान एबीवीपी के प्रांत संगठन मंत्री और कैंट थाना प्रभारी संजय सिंह के बीच झड़प भी हुई, पुलिस की सख्ती पर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि ABVP कार्यकर्ता शिकायत करने पुलिस ऑफिस पहुँच गए, वहां SSP डॉक्टर कौस्तुभ जन सुनवाई कर रहे थे। संगठन के छात्रों ने उनसे घटना के बारे में अवगत कराया। SSP ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कैंट इंस्पेक्टर संजय सिंह को निलंबित कर विभागीय जांच का आदेश दे दिए। विवाद के दौरान एबीवीपी के प्रांत संगठन मंत्री पुनीत अग्रवाल और कैंट इंस्पेक्टर संजय सिंह के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। एक ओर दीक्षा भवन में समारोह चल रहा था, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय परिसर के बाहर सड़क पर पुलिस और परिषद कार्यकर्ताओं के बीच तनावपूर्ण माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था और प्रवेश नियमों के कारण उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। इसे लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की में बदल गई। एक ओर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं दूसरी ओर परिसर के बाहर सड़क पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच विवाद होता रहा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और छात्रों में हाथपाई भी हुई है, इससे आहत संगठन के लोग, एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री अपने अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने पूरे मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की।

कांवड़ यात्रा पर पुलिस सख्त, 12 फीट से ज्यादा ऊंची DJ कांवड़ पर रोक

कांवड़ यात्रा में डीजे के नियमों को लेकर पुलिस अब सख्त हो गई है। सहारनपुर में शासन से तय उंचाई तक की डीजे कांवड़ को ही अनुमति दी जा रही है। 12 फीट से अधिक उंचाई की कांवड़ यात्रा में शामिल ना हो सकें इसके लिए बॉर्डर पर ही बैरियर लगा दिए गए हैं। एसएसपी अभिनंदन पाठक ने बताया कि 12 फीट से अधिक ऊंची कांवड़ को अनुमति नहीं है उन्हे रोका जा रहा है। अगर आप भी डीजे कांवड़ लेकर निकले हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए कुछ मानक तय किए हैं। यूपी सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे कांवड़ की अधिकतम उंचाई 12 फीट हो सकती है। अगर ऊंचाई इससे अधिक है तो ऐसी कांवड़ को बीच रास्ते ही रोक दिया जाएगा। इससे अधिक ऊंचाई की कांवड़ को यूपी में ही प्रवेश नहीं मिलेगा। हरियाणा, पंचाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कावड़ियां के लिए यूपी हरिद्वार जाने का गेट है। इन सभी राज्यों के कांवड़ियां यूपी से होकर ही उत्तराखंड यानी हरिद्वार में प्रवेश करते हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने तय किया है कि 12 फीट ऊंची कांवड़ को ही अनुमति दी जाएगी। इसके लिए अब पुलिस ने कमर कस ली है। दूसरा चरण शुरू होने के बाद अब पुलिस सख्त हो गई है। 12 फीट से अधिक ऊंचाई वाली कांवड़ों को रोका जा रहा है। एसएसपी अभिनंदन सिंह ने कहा कि ऊंचाई इसलिए तय की गई है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। आशंकित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कांवड़ की ऊंचाई 12 फीट तय की गई है। एसएसपी के अनुसार अक्सर यह देखने में आ रहा है कि कांवड़ियां डीजे के ऊपर स्पीकर पर बैठ जाते हैं इससे भी हाइट यानी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए कांवड़ियों को रोका जा रहा है और उन्हे स्पीकर के ऊपर से उतारा जा रहा है। इस सख्ती का उद्देश्य कांवड़ियों की भलाई है। अगर ऊंचाई अधिक रहेगी तो इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी इसलिए कांवड़ियों को 12 फीट से अधिक ऊंची कांवड़ ले जाने से रोका जा रहा है।